Topic 1 :- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)

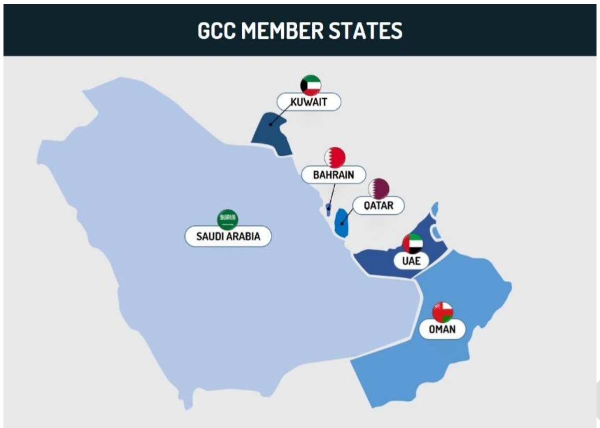

चर्चा में क्यों :- खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने किया अपना 'क्षेत्रीय सुरक्षा विज़न' प्रस्तुत। इस विज़न को दिसंबर 2023 में अपनाया गया ।

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) :-

इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसमें कुल 6 सदस्य देश है । सदस्य देश :- संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कतर और कुवैत) ।

*इस संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य सभी सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना जिससे यह सदस्य देश सभी क्षेत्रों में एक साथ समन्वय बनाकर कार्य कर सके। इस संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों से बनती है जो सर्वोच्च परिषद होती है।

*इसके बाद एक मंत्रिपरिषद स्टार्ट की परिषद होती है जिसमे सभी सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री शामिल होते है।

यह परिषद क्षेत्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए इससे जुड़े एक फ्रेमवर्क को अपनाती है जिसने हिंसा, असहमति और संघर्ष को दूर करने के लिए विशेष उपबंध किए गए है।

परिषद के क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विज़न के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है :-

Result Mitra

1.सदस्य देश जहां एक और विकास के मुद्दे पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का भी ध्यान रखेंगे।

2. इस संगठन के सभी सदस्य देश एक दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे इसके तहत यदि संगठन के किसी भी एक सदस्य को कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो उसे सभी परिषद् के सभी सदस्यों के लिए खतरा माना जाएगा।

3. सदस्य देशों के बीच किसी भी प्रकार का मतभेद या विवाद होने पर उसे सुलझाने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यह सभी विवाद के मुद्दे चर्चा और संवाद के माध्यम से ही सुलझाए जाएंगे।

4.सदस्य देश अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग से बचने तथा चर्चा और संवाद को प्राथमिकता देने हेतु संयुक्त प्रयासों पर बल देंगे।

5.सदस्य देश अपने नियंत्रण के संपूर्ण क्षेत्र को सामूहिक विनाशकारी हथियारों से मुक्त बना कर रखेंगे साथ ही परमाणु अप्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रयासों का समर्थन करेंगे।

6. कोई सदस्य देश किसी भी प्रकार के अमानवीय कृत्य का समर्थम नहीं करेगा और न ही आतंकवाद, उग्रवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी किसी भी गतिविधि को बढावा देगा।

7. सभी सदस्य देश जल व खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक संसाधनों की रक्षा एवं निवेश जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

8.फिलिस्तीनी मुद्दे के उचित समाधान के रूप द्वि-राष्ट्र (2-state) समाधान का समर्थन ।

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन 'खाड़ी सहयोग परिषद' का सदस्य नहीं है? (2016)

(a) ईरान

(b) ओमान

(c) सऊदी अरब

(d) कुवैत

उत्तर: (a)

Result Mitra

Topic 2:- चुनावों को प्रभावित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग

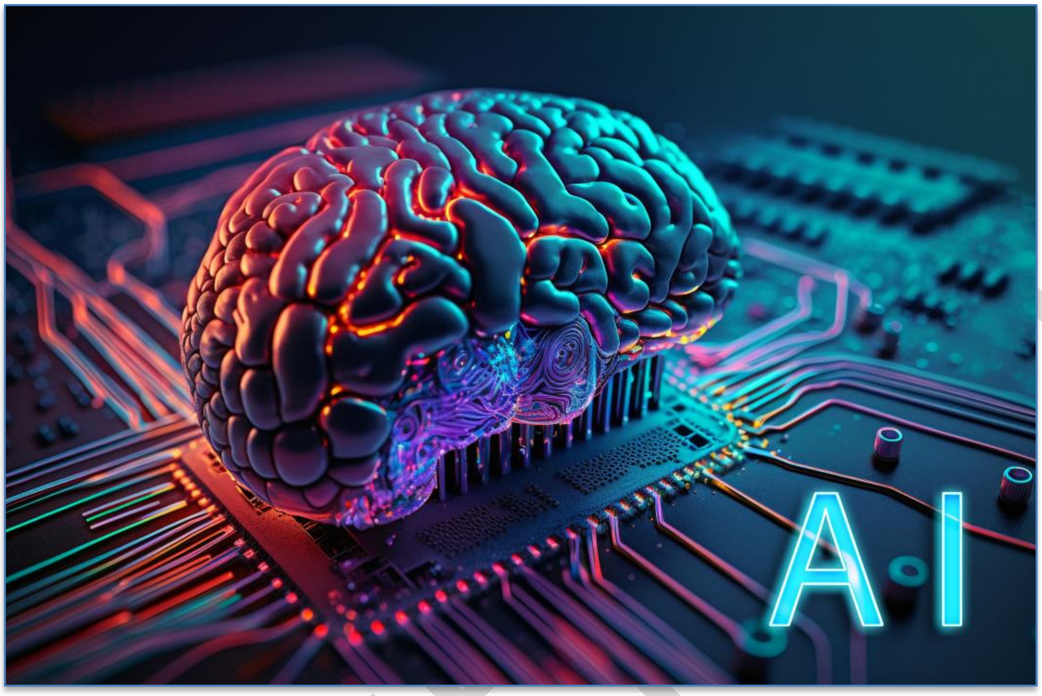

चर्चा में क्यों :- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है :- 'चुनावों में बाधा उत्पन्न करने की नियत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दुरुपयोग'।

रिपोर्ट के उल्लिखित मुख्य बिंदु :-

1. हाल ही में हुए कुछ महत्त्वपूर्ण राष्ट्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग करके उन्हे प्रभावित करने की कोशिश की गई।

उदाहरण के रूप में :-

A. अमेरिका ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया।

B. ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन ने AI का प्रयोग कर अपने विरोधियों के प्रति दुष्प्रचार अभियान चलाने का प्रयास किया।

Result

चुनावों को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जा रहा है :- AI-जनरेटेड एंकर, AI-एनहेंस्ड वीडियो, AI-जनरेटेड ऑडियो, AI-जनरेटेड मीम्स।

चुनावों के लिए AI कैसे खतरा है :-

1. राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रति भ्रामक विज्ञापन और झूठे प्रचार सामग्री का प्रयोग करना।

2.AI के माध्यम वर्तमान में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बयानों को परिवर्तित करके प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे जनमत को भ्रमित किया जा सके।

3.AI का प्रयोग करके मतदाता डेटाबेस , चुनावी अवसंरचना और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है तथा साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न लिए जा सकते है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी भी राष्ट्र के चुनाव को दुनिया के किसी भी देश से नियंत्रित किया जा सकता है और उसे एक विशेष मकसद से परिवर्तित भी किया जा सकता है इससे चुनाव में विदेशी प्रभाव बढ़ने का खतरा रहता है

चुनाव में AI के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है:-

- भारत में चुनावों को A.I. से बचाने के लिए आवश्यक है की सरकार और निर्वाचन आयोग नवीनतम AI प्रौद्योगिकि के विशेषज्ञों को शामिल करें।
- संसद A.I. के हस्तक्षेप को रोकने के लिए कानून बना सकती है।
- मेटा फैक्ट चेकिंग हेल्पलाइन और पीआईबी फैक्ट चेक जैसे उपाय करने की जरूरत जिससे भारत में गलत और भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित करने से रोका जा सके।

Result Mitra

प्रश्न 1. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना

2. सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना

3. रोगों का निदान

4. टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन

5. विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनियेः

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तरः (b)

Result Mitra

Topic 3 :–"जीवन और समानता के अधिकार में "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" सुप्रीम कोर्ट

प्रश्न 1. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर आधारित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिये। (2021)

चर्चा में क्यों :- हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के दिए हुए एक निर्णय पर फिर से सुनवाई कर रहा है जिसके लिए यह अपील सरकार के कुछ मंत्रालय द्वारा की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2021 में देश के दो राज्यों (गुजरात व राजस्थान) से संबधित बिजली कंपनियों को राज्य के अंदर हाई टेंशन बिजली की तारों को पूर्ण रूप से भूमिगत करने का आदेश दिया।

यह निर्णय देने का मुख्य उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जान को बचाना था क्योंकि यह पक्षी इन तारों के संपर्क में आकर क्षतिग्रस्त हो जाते थे

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जिसमें तीन न्यायाधीश है स्वयं के पूर्व निर्णय में संशोधन हेतु दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं

यह याचिका भारत के निम्नलिखित मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गई है :- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मलालय; विद्युत मन्त्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

इस मुद्दे से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय :-

अनुच्छेद 14 जिसमे समानता के अधिकार की बात की गई है और अनुच्छेद 21 जिसमे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है

ये दोनो अनुच्छेद "स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार" तथा "जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार" के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाने जातें है।

Result Mitra

जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तित होने या इसके दुष्प्रभावों से निपटने में वंचित समुदायों की असमर्थता संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत प्रदान किए गए अधिकारों का उल्लंघन है।

संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जिनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से है :-

अनुच्छेद 48A: राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 51A(g): भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदी और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे एवं प्राणी माल के प्रति दयाभाव रखे।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के कुछ ऐसे निर्णय जो पर्यावरणीय समस्याओं को संविधान से जोड़ते हैं :-

वीरेंद्र गौड़ बनाम हरियाणा राज्य वाद: यह वाद वर्ष 1994 में उभर कर आया

इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार" "स्वस्थ जीवन के अधिकार" का एक अभिन्न पहलू या हिस्सा है।

एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ वाद: यह वाद 1996 का है

इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया :- हवा, पानी और मृदा जैसे बुनियादी पर्यावरणीय घटकों में किसी भी तरह के व्यवधान को अनुच्छेद 21 के तहत "जीवन" के लिए नुकसानदेह समझा जाएगा।

Result Mitra

प्रश्न 2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है/प्रतिबिंबित करता है? (2020)

1.प्रस्तावना

2. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

3.मौलिक कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

Result Mitra